लैंड पूलिंग

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

09 मार्च, 2022

लैंड पूलिंग को अनिवार्य बनाने के लिए संशोधन प्रस्तावित

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को अपनी भूमि पूलिंग नीति के क्रियान्वयन में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 में संशोधनों को इसके कार्यान्वयन में तेजी लाने का प्रस्ताव दिया गया है।

प्रस्तावित संशोधनों के माध्यम से, भागीदारी दर 70% की न्यूनतम सीमा तक पहुँचने के बाद, उन मालिकों के लिए भूमि की पूलिंग अनिवार्य हो जाती है, जिन्होंने अभी तक अपनी इच्छा व्यक्त नहीं की है।

साथ ही, पूलिंग को अनिवार्य घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार देने के लिए एक संशोधन प्रस्तावित किया गया है- भले ही 70% की न्यूनतम सीमा हासिल न हो।

श्री पुरी ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता और विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की।

यह पूछे जाने पर कि क्या घोषणाएँ अगले महीने होने वाले नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर की गई हैं, श्री पुरी ने कहा कि पिछले साल से हितधारकों से विचार-विमर्श सहित तैयारी चल रही थी।

लैंड पूलिंग नीति के अनुसार, भूस्वामियों के संघ के गठन के लिए पात्रता प्राप्त करने के लिए एक क्षेत्र में 70% सन्निहित भूमि की आवश्यकता होती है। जबकि विभिन्न क्षेत्रों में मालिकों की भागीदारी 70% को पार कर गई है, सन्निहितता अभी तक हासिल नहीं हुई है, जिसके कारण 2013 में नीति को अधिसूचित किए जाने के बाद से कोई विकास नहीं हुआ है।

"यह (संशोधन) प्रक्रिया को गति देगा क्योंकि शेष बची हुई भूमि योजना का हिस्सा बन जाएगी। डीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, यह भूमि की निकटता के साथ हमारे सामने आने वाली समस्या को भी खत्म कर देगा।

सशर्त नोटिस

इस बीच, डीडीए संशोधनों को मंजूरी मिलने तक कंसोर्टियम के गठन के लिए सशर्त नोटिस जारी करना चाहता है "यह ध्यान में रखते हुए कि प्रस्तावित संशोधनों को उचित विधायी प्रक्रिया का पालन करना होगा, जिसमें समय लगेगा, दूसरी रणनीति भी तैयार की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि डीडीए पात्र क्षेत्रों (जहाँ 70% भूमि पूल की गई है) के लिए संघ के गठन के लिए सशर्त नोटिस जारी करेगा, जिसमें कहा गया है कि संघ कार्यान्वयन योजना को दाखिल करते समय सभी आंशिक रूप से भाग लेने वाले खसराओं की उचित निकटता सुनिश्चित करेगा, "एक प्रेस नोट में कहा गया है।

वर्तमान में लैंड पूलिंग के लिए 104 गाँवों की पहचान की गई है। डीडीए द्वारा भागीदारी की एक मजबूत दर का हवाला देते हुए, एल, एन और पी-द्वितीय क्षेत्रों में कुल 16 उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. लैंड पूलिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह सरकारी एजेंसियों द्वारा भूमि के पार्सल पर बुनियादी ढांचे का विकास / डिजाइन करना है।
2. विकास के बाद भूमि का पूरा पार्सल विभिन्न परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए मूल मालिक को वापस कर दिया जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(क) केवल 1
(ख) केवल 2
(ग) 1 और 2 दोनों
(घ) कोई नहीं

Expected Question (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements regarding land pooling.

1. It is developing/designing infrastructures on parcel of lands by government agencies.
2. The entire parcel of land after development is returned to the original owner to execute various projects.

which of the above statements is/are correct?

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) None

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. लैंड पूलिंग क्या है? इससे जुड़े विभिन्न लाभों और चुनौतियों की चर्चा करें। (250 शब्द)

Q. What is land pooling? Discuss the various benefits and challenges associated with it. (250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।